गुजरात के आर्थिक विकास हेतु केन्द्रीय सहायता

1874. श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य के आर्थिक विकास के लिये केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता मांगी गई है और पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार उस राज्य को और सहायता देने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा यह सहायता कब तक दे दी जायेगी ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) राज्यों को सामान्य केन्द्रीय योजना सहायता का आवंटन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित फार्मूला तथा मानदंड के आधार पर किया जाता है । पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात के लिये सामान्य केन्द्रीय योजना सहायता (निवल) का आवंटन निम्नलिखित है:-

वर्ष	राशि (करोड़ रु०)
1991-92	204.01
1992-93	216.00
1993-94	235.00

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Per Capita G.N.P. in India

1875. SHRI K. R. MALKANI: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government are aware that according to the latest World bank report (*Vide* The Hindu of 21.6.1994), the per capita GNP by Purchasing Power Parities, calculated in "current international dollars", is $ 2,810 for Sri Lanka, $ 2,130 or Pakistan, $ 1,230 or Bangaladesh and only $1,210 in India;

(b) how Government account or the continuing lag of the Indian economy; and

(c) what is proposed to be done to improve production, productivity and employment, to raise the per capita G.N.P. in India?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) Yes, Sir.

(b) Differences in per capita income of different countries depend on a variety of factors, some among them being initial endowments, historical course of events, economic system and policies. India has made considerable progress since independence.

(c) The growth oriented policies of the Government investments and programmes under the Eighth Five Year Plan and the process of ongoing economic reforms will increase production, productivity and employment and thus help raise the per capita G.N.P. in India.